SHRI T.R. BAALU: We will try to complete it within one year. ... (*Interruptions*)...

SHRI S.P.M SYED KHAN: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the Government has any proposal of four laning of Madurai-Cochin road and also the Dindigul-Sabarimala road to avoid heavy traffic during Sabarimala season. If it is so, I would like to know whether any fund has been allotted for the above projects.

SHRI T.R. BAALU: Sir, I am sorry to say that there is no such proposal.

उड़ीसा में संचार सेवाओं का विस्तार

*167. **श्री कृपाल परमार:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि उड़ीसा में संचार सेवाएं शिथिल हैं और उनका विस्तार बहुत धीमी गति से हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में तीव्र गति से संचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं और उनके क्या परिणाम रहे;

(ग) उड़ीसा को शत प्रतिशत संचार सेवा के अधीन कब तक लाये जाने की संभावना है; और

(घ) अभी तक इस लक्ष्य को प्राप्त न किए जाने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

दूरसंचार विभाग से संबंधित उत्तर

(क) उड़ीसा में (उन 4,899 गांवों को छोड़कर जिनको उपग्रह टर्मिनलों से जोड़े जाने की आवश्यकता है) सभी गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान करके सार्वजनिक दूरसंचार सेवाएं सुलभ कराई गई हैं। इसके अलावा, जिन 936 गांवों की जनसंख्या 2000 से अधिक है और वहां सार्वजनिक फोन सुविधा नहीं है, उन गांवों में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) की सहायता से दूसरे वीपीटी के रूप में ग्रामीण सामुदायिक फोन (आरसीपी) प्रदान किया जाएगा। इनमें से 357 आरसीपी प्रदान किए जा चुके हैं और शेष बचे आरसीपी सितंबर 2007 तक प्रदान कर दिए जाएंगे।

31 मार्च 1999 की स्थिति के अनुसार कुल टेलीफोन कनेक्शनों की जो संख्या 3,44,206 थी वह 30 जून, 2005 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 14,84,248 कनेक्शन हो गई है जो कि 27% की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्शाती है।

(ख) से (घ) उड़ीसा में 120 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में से 24 एसडीसीए वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य हैं जहां विभिन्न प्रचालकों द्वारा सेवाएं प्रदान किए जाने की संभावना है। वाणिज्यिक दृष्टि से अव्यवहार्य शेष 96 एसडीसीए के लिए यूएसओएफ ने इन क्षेत्रों में जनवरी, 2006 से मांग पर टेलीफोन प्रदान करने के लिए बीएसएनएल के साथ करार किया है (इनमें दूरदराज के और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित 4899 वे गांव शामिल नहीं हैं जहां नवंबर, 2007 तक समयबद्ध रूप से उपग्रह माध्यम पर वीपीटी प्रदान किए जाने हैं)।

डाक विभाग से संबंधित उत्तर

(क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में डाकियों के माध्यम से दरवाजे पर हर रोज डाक बांटने तथा टिकटों और लेखन सामग्री की बिक्री के संबंध में उड़ीसा सहित देश भर में डाक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि पत्रों के संग्रहण का कार्य लेटर-बॉक्सों के जरिए किया जाता है जो 300 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तथापि, डाकघर दूरी, जनसंख्या और आय संबंधी मानकों की पूर्ति के अध्यधीन ही खोले जाते हैं। सर्किल में 8175 डाकघर हैं जो 5254 ग्राम पंचायतों में से 5097 ग्राम पंचायतों को कवर करते हैं। शेष 157 ग्राम पंचायतों को पंचायत संचार सेवा केन्द्र उपलब्ध कराए गए हैं जो डाक टिकटों और लेखन सामग्री की तथा पत्रों के पंजीकरण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। सर्किल में 208 पंचायत संचार सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

उड़ीसा में डाकघर औसतन 4491 जनसंख्या वाले क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है जो 6592 व्यक्तियों पर एक डाकघर के राष्ट्रीय औसत की तुलना में बेहतर है। उड़ीसा में एक डाकघर द्वारा औसतन 19.08 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में सेवा प्रदान की जाती है जो 21.11 वर्ग किमी प्रति डाकघर के राष्टीय औसत की तुलना में बेहतर है।

सभी 35 प्रधान डाकघरों औरर 144 महत्वपूर्ण उप-डाकघरों में कंप्यूटर और संबंधित उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं तथा इन डाकघरों में प्रचालन कंप्यूटरीकृत है। इसके अतिरिक्त मनीऑर्डरों को शीघ्र पहुंचाने के लिए 5 वेरी स्मॉल ऐपर्चर टर्मिनल (वी सैट), उपग्रह मनीऑर्डर स्टेशन (एसएमओ) और 39 विस्तारित उपग्रह मनीऑर्डर स्टेशन (ईएसएमओ) स्थापित किए गए हैं।

उड़ीसा राज्य 5 राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्रों और 32 राज्य स्पीड पोस्ट केंद्रों के नेटवर्क से भी जुड़ा है। सभी 30 जिले स्पीड पोस्ट नेटवर्क से जुड़े हैं।

(ग) और (घ) डाकघरों को खोलना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डाकघर जनसंख्या, दूरी और आय संबंधी मानदंडों को पूरा करने तथा संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन खोले जाते हैं। अत: शेष ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोलना उन गांवों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर निर्भर करता है।

Expansion of communication services in Orissa

†*167. SHRI KRIPAL PARMAR: Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that communication services in Orissa are in bad condition and their expansion is taking place at a very slow pace;

(b) the efforts made by Government to provide communication services at a fast speed in the State and what is the outcome thereof;

(c) by when Orissa is likely to be brought under cent-per cent communication services; and

(d) the reasons for not achieving this target till now?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI DAYANIDHI MARAN): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Reply pertaining to Department of Telecommunications

(a) All the villages in Orissa have public access to telecom services through provision of a Village Public Telephone (VPT) (except 4,899 villages which need to be connected with satellite terminals). Additionally 936 villages with population exceeding 2000 and without a public phone facility will be provided with a Rural Community Phone (RCP) as a second VPT with the support from Universal Service Obligation Fund (USOF). Out of these, 357 RCPs have already been provided and remaining will be provided by September, 2007.

The total number of telephone connections have increased from 3,44,206 as on 31st March, 1999 to 14,84,248 connections as on 30th June, 2005 representing a Compounded Annual Growth Rate (CAGR) of 27%.

†Original notice of the question was received in Hindi.

(b) to (d) In Orissa out of 120 Short Distance Charging Areas (SDCAs), 24 SDCAs are commercially viable where market forces are expected to cater to provide the services. For the remaining 96 commercially unviable SDCAs, USOF has entered into agreement with BSNL for providing telephone on demand in these areas from January, 2006 (this excludes 4,899 villages in remote and inaccessible areas where VPTs are to be provided on satellite media in a time bound fashion by November, 2007).

Reply pertaining to Department of Posts

(a) and (b) Postal facilities in terms of daily delivery of dak at the doorstep and sale of stamps and stationery through postmen in rural areas is available throughout the country, including Orissa, while collection of letters is being done through letter boxes which are being provided in villages with population exceeding 300. Post offices are however opened only subject to fulfilment of distance, population and income norms. There are 8175 Post Offices in the Circle covering 5097 out of 5254 Gram Panchayats. The remaining 157 Gram Panchayats have been provided with Panchayat Sanchar Sewa Kendras which provide facilities for sale of stamps and stationery and registration of letters. There are 208 Panchayat Sanchar Sewa Kendras functioning in the Circle.

In Orissa, one Post Office serves an average population of 4491, which compares favourably with the national average of 6592 per Post Office. The average area covered by one Post Office in Orissa is 19.08 Sq. Kms., which compares favourably with the national average of 21.11 Sq. Kms. per Post Office.

All the 35 Head Post Offices and 144 important Sub Post Offices have been provided with Computers and peripherals and operations in these Post Offices are computerized. Further 5 Very Small Aperture Terminal (VSAT), Satellite Money Order stations (SMO) and 39 Extended Satellite Money Order stations (ESMO) have been established for faster transmission of Money Orders.

Orissa State is also linked through a network of 5 National Speed Post centres and 32 State Speed Post centres. All 30 Districts are connected to the Speed Post network.

(c) and (d) The opening of Post Offices is an ongoing process. Post Offices are opened, subject to fulfilment of population, distance and income norms and subject to availability of resources. Therefore provision of post offices in the remaining Gram Panchayat villages is dependent on their fulfilling the prescribed norms.

श्री कृपाल परमार: माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है और प्रदेश की संचार स्थिति की जो हालत बयान की है, अगर उसको सच भी मान लिया जाए, तब भी इनके उत्तर के मुताबिक 4899 ऐसे गांव हैं, जिनको अभी संचार सुविधाएं देने का प्रयास ही नहीं किया गया है। जिन 936 गांव्रों की जनसंख्या 2000 से अधिक है, अगर उनको भी इनके साथ जोड़ा जाए तो यह उड़ीसा के लगभग 58 हजार गांवों का लगभग 10 फीसदी बनता है। जहां तक इनमें से कुल 600 गांवों को 2007 तक ये सुविधाएं देने की बात कही गई है, मान्यवर जिन 90 फीसदी गांवों में टेलीफोन उपलब्ध भी करवाए गए हैं, उनमें से अधिकांश टेलीफोन खराब पड़े हुए हैं। एक पंचायत में नाम मात्र एक टेलीफोन लगाने पर भी उसे टेलीफोन से जुड़ा हुआ माना गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो आंकड़ा 4899 गांवों का दिया है, जिनको उपग्रह टर्मिनलों के साथ जोड़ा जाना है, वे कब तक इन टर्मिनलों को संचार से जोड़ेंगे?

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, first of all, I would like to tell the hon. Member that the information given by me is not distorted. Sir, I have given whatever information is available to me. Sir, based on the data that I have with me, I would like to say that there are about 40,753 village public telephones operating in Orissa till June of this year. Now, as far as the question of the hon. Member as to when the remaining 4,899 villages would be connected, Sir, I would like to say that we will be connecting them by 2007. The reason why we have not been able to do it so far is this. Sir, the national average is around 9.7. The hon. Member is right. I will not say that Orissa is very well connected. Orissa's average is 4.7. It is about 50 per cent of the national average. Sir, the reason that the villages are not connected in Orissa, the remote parts, is because the areas are inaccessible and, moreover, Sir, there is no power supply. We need proper power supply to have our telephone exchanges functioning properly. We try to cover most of the rural areas with WLL. The WLL is the fastest and the easiest way to connect areas. But the people are not able to use their phones because they are not able to charge their phones as there is no electricity available. As far as the village public telephone is concerned, it is only one per phone. That is why it is called VPT. That is what we have been providing.

श्री कृपाल परमार: सभापति जी, उड़ीसा में बीएसएनएल के मोबाइल फोन्स की कनेक्टिविटी में सुधार की जरूरत है और कनेक्टिविटी न होने के कारण बीएसएनएल के उपभोक्ता दूसरी कम्पनियों की ओर स्विच ओवर कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय बीएसएनएल के उपभोक्ताओं को ठीक से मोबाइल कनेक्टिविटी देने का प्रयास करेंगे और कब तक?

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, I would like to tell the hon. Member that in last one year alone, we have added about three lakh new telephone

connections in Orissa. Sir, there are about 14 lakh connections in Orissa. Sir, by the end of this year, we will be adding, the BSNL alone will be adding about 7.95 lakhs additional phones, including 40,000 WLL connections. This is only the BSNL's data. I am sure, the private operators will also add to this number. So, we are expecting that somewhere around 12 lakh phones are to be added in Orissa by this year. Sir, nearly 95 per cent of the existing connections are to be added in the coming year.

श्री सुरेन्द्र लाठः सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अपने रेप्लाई में कहा है कि उड़ीसा में 14,84,248 फोन हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन 14,84,248 फोन्स में से कितने फोन डब्लूएलएल में हैं और कितने फोन मोबाइल्स में हैं? इन फोन्स के बाद लैंड लाइन फोन्स में कितने वेटिंग लिस्ट में हैं। डब्ल्यूएलएल फोन में कितनी वेटिंग लिस्ट है? इन सबके बाद फोन ऑन डिमांड वे कब तक आरंभ करने वाले हैं?

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, I have the data with me. The total number of landline phones is 7,66,391, the number of WLL phones is 97,749, the number of mobile phones is 6,20,188. That comes to a total of 14,84,248. There is a waiting list of around 45,000 in Orissa. But, Sir I would like to say that we are into the process, and we are looking very positively at adding nearly about 7.5 lakhs by December this year. The hon. Member may rest assured that we are looking at Orissa and we shall definitely try to increase the connectivity in Orissa.

Level of scientific research in the country

*168. SHRI MANOJ BHATTACHARYA:
SHRI C. RAMACHANDRAIAH:

Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the recent media reports that the Indian Scientist is a case of pointless and indolent research;

(b) if so, Government's reaction thereto; and

(c) the steps to be taken to rejuvenate the level of scientific research in the Universities and various scientific institutes of excellence and make them professionally useful for developing technology?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.